



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1939 (श10)

(सं० पटना 252) पटना, मंगलवार 20 मार्च 2018

सं० 6/पणन (सं०)—76/2015—457  
सहकारिता विभाग

संकल्प

12 फरवरी 2018

**विषय :** वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता के 80 विद्युत आधारित चावल मिल (झायर के साथ) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल लागत रु. 61.96 करोड़ रुपये (एकसठ करोड़ छियान्वे लाख) का 60% केन्द्रीय हिस्सा तथा 40% राज्य हिस्सा प्राप्त कर सहकारी बैंकों के माध्यम से उक्त सहकारी समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में।

राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, पैक्सों/व्यापारमंडलों के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तथा पूर्व के चावल मिल—सह—गैसीफायर संयंत्र की गुणवत्ता तथा कार्य निष्पादन के मद्देनजर तथा विद्युत आपूर्ति में वृद्धि के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में कुल 80 विद्युत आधारित 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता के चावल मिल (झायर के साथ) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय-सीमा**।— राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में 2017-18 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता वाले चावल मिल (झायर के साथ) स्थापित कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रति इकाई 77.45 लाख (चावल मिल—59.45 लाख एवं ज़ायर—18.00 लाख) की लागत से 80 चावल मिल (झायर के साथ) की स्थापना पर कुल 61.96 करोड़ रुपये व्यय होगा। चावल मिल (झायर के साथ) स्थापित करने की अवधि एक वर्ष की होगी।

एतद् संबंधी एक विवरणी निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य		अभ्युक्ति
		क्षमता (2मे.टन/घंटा)	बिजली आधारित चावल मिल की संख्या		प्रति इकाई लागत झायर के साथ (लाख में)	कुल लागत (करोड़ में)	
			समिति	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2017-18	2 मे.टन/घंटा	पैक्स/ व्यापारमंडल	80	77.45 (59.45+18.00)	61.96	

- वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्र एवं राज्य के बीच 50:50 के अनुसार राशि व्यय की नई व्यवस्था की गयी थी किन्तु इस व्यवस्था को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनः संशोधित कर केन्द्र एवं राज्य के बीच 60:40 के अनुसार व्यय की नई व्यवस्था की गयी है।
3. **वित्तीय स्रोत** :- पैक्सों/व्यापारमंडलों में विद्युत आधारित चावल मिल (झायर के साथ) की स्थापना हेतु आवश्यक निधि कुल रु. 61.96 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) के अन्तर्गत केन्द्रांश (37.176 करोड़ रुपये) एवं राज्यांश (24.784 करोड़ रुपये) मद में कर्णांकित राशि से पैक्सों/व्यापारमंडलों को सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषि विभाग द्वारा आर.के.वाई.भी. अन्तर्गत सामान्य, SCP एवं TSP मद में अलग-अलग राशि कर्णांकित किया गया है। इस कर्णांकित राशि का उपयोग करने हेतु पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए किये गये आरक्षण को आधार बनाया जायेगा और चयनित पैक्सों में उसी आधार पर उसी श्रेणी को आरक्षण का लाभ देते हुए चावल मिल (झायर के साथ) का निर्माण कराया जायेगा। व्यापार मंडलों में भी तदनुसार आरक्षण के अनुसार चावल मिलों का निर्माण कराया जायेगा।
4. **चक्रीय पूँजी की वापसी** :- योजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों में विद्युत आधारित चावल मिल (झायर के साथ) की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी योजना पूर्ण होने के अगले वर्ष से 10 वर्षों में 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में की जा सकेगी। चक्रीय पूँजी की उक्त वापसी की राशि से एक Revolving Fund का सृजन तथा संधारण किया जायेगा। Revolving Fund की राशि का उपयोग सहकारी समितियों के आधारभूत संरचनाओं के रख-रखाव हेतु अलग से योजना तैयार कर इसी प्रकार की चक्रीय पूँजी समितियों को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा।
- पैक्सों/व्यापारमंडलों को विद्युत आधारित चावल मिल (झायर के साथ) की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा जिसमें दी गई चक्रीय पूँजी का ब्योरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी पूरा ब्योरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्योरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
5. **भूमि की व्यवस्था** :- पैक्सों में स्थापित होने वाले विद्युत आधारित चावल मिल (झायर के साथ) की स्थापना हेतु भूमि पैक्सों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना है। इस क्रम में पैक्सों के पास पूर्व से उपलब्ध जमीन अथवा दान के माध्यम से अथवा पैक्सों के द्वारा अपने संसाधन से खरीदी अथवा लीज पर ली गई जमीन का उपयोग हो सकेगा।
- समितियों का चयन** :- विद्युत आधारित चावल मिल (झायर के साथ) की स्थापना हेतु पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन जिला स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- कार्यान्वयन एजेन्सी** :- पैक्स/व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा स्वयं या निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
- तकनीकी पर्यवेक्षण** :- परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन पर भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है, उसे लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत Structural Design तथा प्राक्कलन जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में तकनीकी पर्यवेक्षण Third Party Consultant/Open Market से कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा असेैनिक कनीय अभियंताओं का चयन किया जायेगा, जिन्हें प्रति इकाई विद्युत आधारित चावल मिल (झायर सहित) के प्राक्कलन के अनुसार असेैनिक कार्यों के लागत का 2.5% मानदेय दिया जायेगा, जो विद्युत आधारित चावल मिल (झायर सहित) के कुल लागत के अन्तर्गत होगा। इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के स्तर से एक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।
- अनुश्रवण** :- जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा।

6. **योजना का कार्यान्वयन** ।— वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल लागत रु. 61.96 करोड़ रुपये (एकसठ करोड़ छियान्चे लाख) का 60% केन्द्रीय हिस्सा तथा 40% राज्य हिस्सा प्राप्त कर सहकारी बैंकों के माध्यम से उक्त सहकारी समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराते हुए 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता के 80 विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना की जायेगी।
7. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निदेश लागू होगा।
8. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**सुरेश चौधरी,**  
 सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 252-571+20-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>